

भारत का मध्यावधि विकास परिदृश्य: आशापूर्ण दृष्टि और उम्मीद के साथ

भारत के आर्थिक इतिहास में वर्ष 2014-2022 एक महत्वपूर्ण अवधि रही है। अर्थव्यवस्था व्यापक संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के दौर से गुजरी, जिसमें अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता बढ़ी और अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत सशक्त हुए। यह प्रणाली ईज ऑफ लिविंग एंड ड्रूइंग बिजनेस के सुधारों पर बल देने सहित सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण, विश्वास-आधारित शासन को अपनाने, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-भागीदारी और कृषि उत्पादकता में सुधार के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित थी। सामान्य परिस्थितियों में, इस तरह के पैमाने और प्रासंगिक सुधारों से आर्थिक विकास में तेजी आएगी। हालांकि, मोटे तौर पर पिछले वर्षों में क्रेडिट बूम के फलस्वरूप बैलेंस शीट के दबाव के कारण और दूसरी बार के वैश्विक संकटों के कारण, प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक वैरिएबल, जैसे कि क्रेडिट ग्रोथ, पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, कुछ सुधारों के परिणाम आने में देरी होती है चूंकि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार के सुधारों के प्रसार में समय लगता है।

यह स्थिति 1998-2002 की अवधि के अनुरूप है क्योंकि उस समय भी सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों ने अर्थव्यवस्था में अस्थायी आघातों के कारण विकास प्रतिकूल को कम कर दिया था। आघातों के कम होने के बाद संरचनात्मक सुधारों ने 2003 से विकास लाभांश का प्रतिकूल देना शुरू कर दिया था। इसी तरह, वर्तमान दशक में, मजबूत मध्यावधि ग्रोथ मैग्नेट्स से हमें आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है और उम्मीद है कि एक बार जब महामारी के वैश्विक आघातों के कारण 2022 में वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में तेजी से बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्रों की बेहतर और स्वस्थ बैलेंस शीट के साथ, एक नया ऋण-चक्र (क्रेडिट साईकल) पहले ही शुरू हो चुका है, जो पिछले महीनों में बैंक ऋण में दो अंकों की वृद्धि से स्पष्ट झलकता है। इसके अतिरिक्त, अधिक औपचारिकता, उच्च वित्तीय समावेशन, और डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक सुधारों द्वारा मिले आर्थिक अवसरों के परिणामस्वरूप दक्षता लाभ से अर्थव्यवस्था को फायदा मिलना शुरू हो गया है। इस प्रकार, भारत का विकास दृष्टिकोण पूर्व-महामारी के वर्षों की तुलना में बेहतर प्रतीत होता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यावधि में अपनी क्षमता से बढ़ने के लिए तैयार है।

परिचय

2.1 भारत पिछले आठ वर्षों के दौरान नए युग के सुधारों के क्रान्तिकारी परिवर्तन से गुजरा है। इन सभी विविध सुधारों से अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार होता है और इसके संभावित विकास को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था और उसके लोगों की उत्पादक क्षमता को उजागर करने के व्यापक नीतिगत लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन सुधारों का उद्देश्य, मौलिक स्तर के जीवनयापन और व्यापार करने में सुविधा को बढ़ाना है। विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुधारों को रेखांकित करता है। सुधारों से मिली आर्थिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिकता के फलस्वरूप तीव्र गति से विकास हुआ, परन्तु घरेलू वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग

और गैर-बैंकिंग) अधिक वरीयता दी और कॉपोरेट क्षेत्र; वह दूसरा क्षेत्र था, जिसने एक बार के वैखिक आघातों का सामना किया।

2.2 देश में शुरू किए गए स्थायी संरचनात्मक और शासन सुधारों की गति और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता, भारत के मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण को नियंत्रित करना आवश्यक है। क्या एक बार के आघातों को उभरने के बाद अर्थव्यवस्था स्थिर विकास दर हासिल कर लेगी और उसे बनाए रखेगी? इस अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया गया है और इसका यह निष्कर्ष है कि भारत की अपनी क्षमता संबंधी संवर्धन और संभावित विकास को बढ़ाने की संभावना पिछले दो दशकों की तुलना में अधिक है। यह अध्याय पिछले तीन दशकों में भारत के उत्पाद और पूंजी बाजार सुधारों के इतिहास की संक्षिप्त चर्चा के साथ शुरू होता है। इनमें आगे चलकर 2014 से 2022 तक किए गए ऐतिहासिक सुधारों की व्यापक को सोच दर्शाया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था को इस अवधि के दौरान लगे आघातों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय के अंत में भारत के मध्यावधि विकास मैग्नेट्स पर चर्चा की गई है।

उत्पाद और पूंजी बाजार में सुधार

सुधारों की शुरुआत- 1991

2.3 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ के मैक्रोइकॉनॉमिक असंतुलन को लेकर सरकार ने 1991 के संरचनात्मक सुधारों को शुरू किया। केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च संयुक्त घाटे, बढ़े हुए मुद्रास्फीति के दबाव, और बड़े और अस्थिर चालू खाता घाटे (सीएडी) के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन का संकट¹ पैदा हुआ। इस स्थिति के जवाब में, वर्ष 1991 में व्यापार और निवेश को उदार बनाया गया। लगभग सभी मध्यवर्ती इनफट और पूंजीगत वस्तुओं के आयात लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया और फर्मों के लिए प्रवेश प्रतिबंधों को सरल बना दिया गया। नई नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र कई क्षेत्रों में के एकाधिकार को समाप्त किया और 51 प्रतिशत तक एफडीआई के लिए स्वतः अनुमोदन नीति शुरू करके निजी क्षेत्र की फर्मों के प्रवेश के लिए प्रोत्साहित किया। विनिमय दर को लचीला बनाया गया और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार मूल्यहास की अनुमति दी गई। रुपये को चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय और पूंजी खाते पर आंशिक रूप से परिवर्तनीय बना दिया गया। इन सुधारों से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। वास्तविक वृद्धि 1980 के दशक के दौरान औसतन 5.5 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 93 से वित्त वर्ष 2000 तक 6.3 प्रतिशत हो गई। बाह्य व्यापार पर व्यापार उदारीकरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ा क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद के लिए कुल माल और सेवा व्यापार वर्ष 1990 के 17.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2000 में 30.6 प्रतिशत हो गया।²

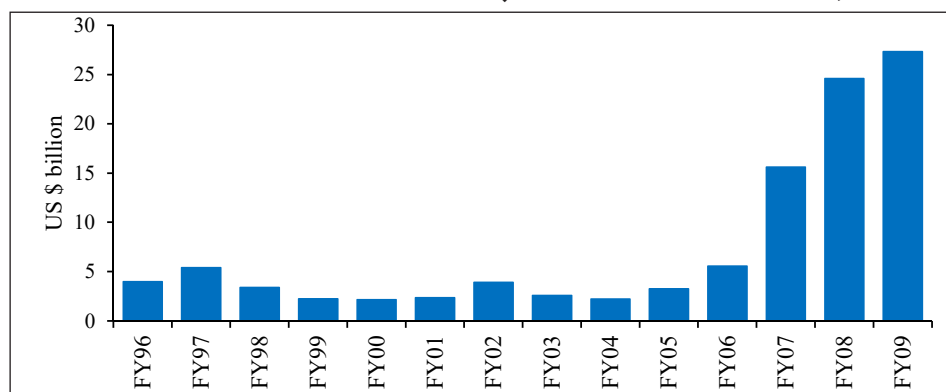
नए उत्साह के साथ सुधारों में निरंतरता

2.4 1990 के दशक के दौरान उत्पाद और पूंजी बाजार के सुधार धीरे-धीरे जारी रहे। उन्हें सरकार से दशक के अंत में एक नवीकृत प्रोत्साहन मिला। गैर-ऋण-सृजन पूंजी प्रवाह के मुख्य स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश को और अधिक उदार बनाया गया (चित्र 1)। नई दूरसंचार नीति 1991 द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में संपूर्ण सुधार किया गया। सशक्त विनियामक व्यवस्था (ट्राई) के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया गया था। इन सुधारों ने सरकार के लाइसेंसिंग और नीति संबंधी कार्यों को ऑपरेटर (बीएसएनएल) से अलग कर दिया। ये सुधार भारत के आईटी क्षेत्र में आने वाली तेजी की आधारशिला थी और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए अधिक व्यापक लाभकारी थे। इस अवधि के दौरान विनिवेश और निजीकरण की नीति ने भी गति पकड़ी। सरकार ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक समर्पित मंत्रालय का गठन किया। इसने कुछ सीपीएसई और निजीकृत कंपनियों जैसे मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्युमिनियम और विदेश संचार निगम लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी बेची।

¹भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास-खंड IV (<https://www.rbi.org.in/scripts/RHvol-4.aspx>)

²श्री अरविंद पनगढ़िया, 2004। “1980 और 1990 के दशक में भारत: सुधारों की जीत,” आईएमएफ वर्किंग पेपर्स 2004/043, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2004/wp0443.pdf>)

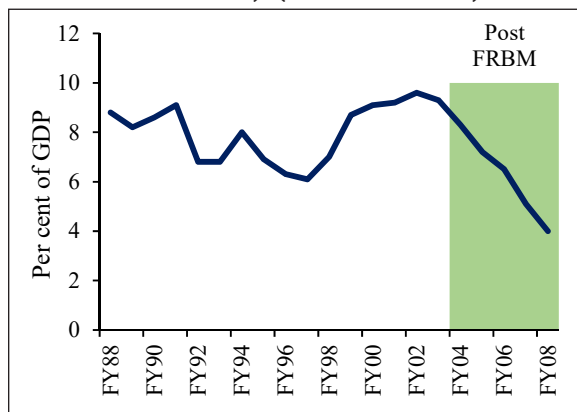
चित्र II.1 वर्ष 2000-2003 में निवेश के उदारीकरण को बढ़ावा देने के बाद भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि



स्रोत: आरबीआई

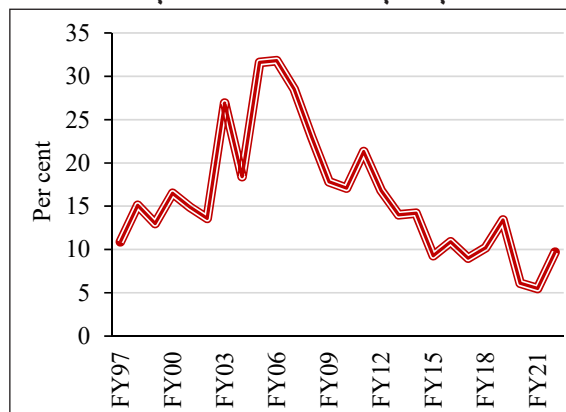
2.5 इस अवधि में स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना, 'स्वर्णिम चतुर्भुज' की शुरुआत भी हुई। इस परियोजना से बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर औद्योगिक गतिविधि, व्यापार और आर्थिक विकास के माध्यम से देश को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ हुआ।³ इसके साथ ही व्यापक आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए ढांचागत नीतियां बनाई गईं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम सरकार के संयुक्त सकल राजकोषीय घाटे के ऐतिहासिक उच्च स्तर से निपटने के लिए पारित किया गया था (चित्र II.2)। बैंकिंग प्रणाली, जिसने 1991 के सुधारों के बाद आर्थिक पुनरुत्थान की अवधि के दौरान अशोध्य ऋण जमा कर लिया था, को ब्याज दरों के अविनियमन और सरफेसी अधिनियम 2002 के अधिनियमन के माध्यम से समर्थित किया गया था। बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, जमाकर्ताओं को अधिक बैंकिंग विकल्प देने और मौद्रिक नीति संचरण को मजबूत करने के लिए ब्याज दरों को अविनियमित किया गया।⁴ सरफेसी अधिनियम ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अदालतों/न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना उधारकर्ता/गारंटर की सुरक्षित संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करके अपना बकाया वसूलने की अनुमति दी।⁵ इन दोनों सुधारों ने अर्थव्यवस्था में ऋण की स्थिति में सुधार किया (चित्र II.3)।

चित्र II.2: सकल राजकोषीय घाटा (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) (जीडीपी का %)



स्रोत: आरबीआई

चित्र II.3: कुल संपत्ति के : के रूप में एससीबी का सकल एनपीए



स्रोत: आरबीआई

³गनी, एजाज एंड ग्रोवर, आरती एंड केर, विलियम। (2012)। सफलता का मार्ग: भारतीय विनिर्माण के स्थान और प्रदर्शन के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का प्रभाव। द इकोनॉमिक जर्नल। (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/econj.12207>)

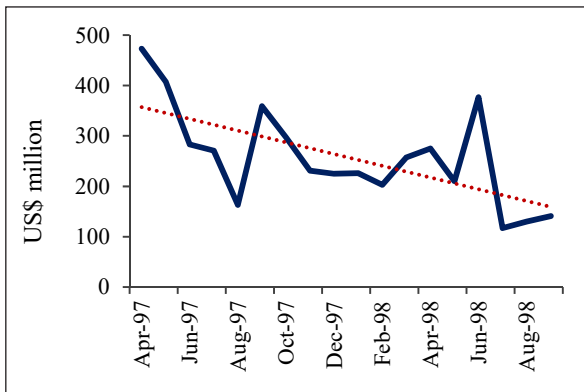
⁴भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, 2011. "बचत बैंक जमा ब्याज दर का अविनियमन: एक चर्चा पत्र," बैंकिंग पेंपर्स आईडी: 3959, ईसोशलसाइंसेज। (<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DPS2770411F.pdf>)

⁵विनोद कुमार, और राजीव खोसला। (2017)। सरफेसी अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन और प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसंधान जर्नल (IERJ), 3(5)। <https://ierj.in/journal/index.php/ierj/article/view/863/869> <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1578808>

एक आघात से 1998-2002 के सुधार हो गए

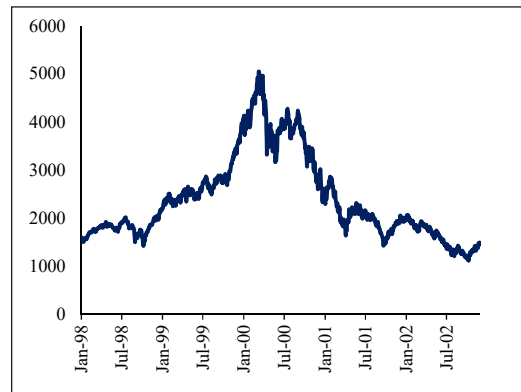
2.6 इन सुधारों की अवधि में घरेलू और वैश्विक आघातों की एक श्रृंखला भी देखी गई, जिसने निवेशकों के विश्वास को कमजोर कर दिया। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण परमाणु परीक्षणों के बाद के महीनों के दौरान भारत में पूंजी प्रवाह में तेजी से गिरावट आई (चित्र II.4)⁶¹। वर्ष 2000 और 2002 के बीच की अवधि में लगातार दो सूखे भी देखे गए (तालिका II.1)। इन घरेलू आघातों से तकनीकी में आए उछाल की समाप्ति और 9/11 के हमलों (चित्र II.5) के परिणामस्वरूप बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताएँ थीं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान भारतीय वित्तीय प्रणाली और कॉर्पोरेट क्षेत्र के तुलन-पत्र को ठीक किया जा रहा था (चित्र II.5)। हालांकि इन सभी कारकों ने सरकार द्वारा किए गए सुधारों के तत्काल प्रभाव को कम कर दिया, लेकिन उन्होंने इसकी आधार रखा और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक उछाल में भाग लेने के लिए संरचनात्मक रूप से तैयार किया, जो इसके तुरंत बाद फलीभूत हुआ।

Figure II.4: Monthly Foreign Direct Investment came down (1998)



स्रोत: आरबीआई

Figure II.5: Trends in the NASDAQ Composite index (Dot-Com Bubble crisis)



स्रोत: एफआईडी

तालिका 1: वर्ष 2000 और 2002 के बीच भारत में सूखे की घटना, प्रभावित लोगों की संख्या और नुकसान

तारीख	स्थान	संख्या
अप्रैल 2000	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र	प्रभावित-9 करोड़; नुकसान- 588,000,000 अमेरिकी डॉलर
नवंबर 2000	महासमुंद्र, रायपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग जिले (छत्तीसगढ़ क्षेत्र)	
मई 2001	नई दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा	20 मौत
जुलाई 2002	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु	प्रभावित-30 करोड़; नुकसान-910,721,000 अमेरिकी डॉलर

स्रोत: सामरा, जे.एस., 2004 “भारत में सूखे की निगरानी, घोषणा और प्रबंधन की समीक्षा और विश्लेषण,” आईडब्ल्यूएमआई वर्किंग पेपर्स H035617] अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। (<https://www.preventionweb.net/files/1868.VL102135.pdf>)

⁶¹डेनियल मॉरो और माइकल कैरियर) 1999 (भारत और पाकिस्तान पर 1998 के प्रतिबंधों के आर्थिक प्रभाव, अप्रसार समीक्षा, 6:4, 1-16)। (<https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf>)

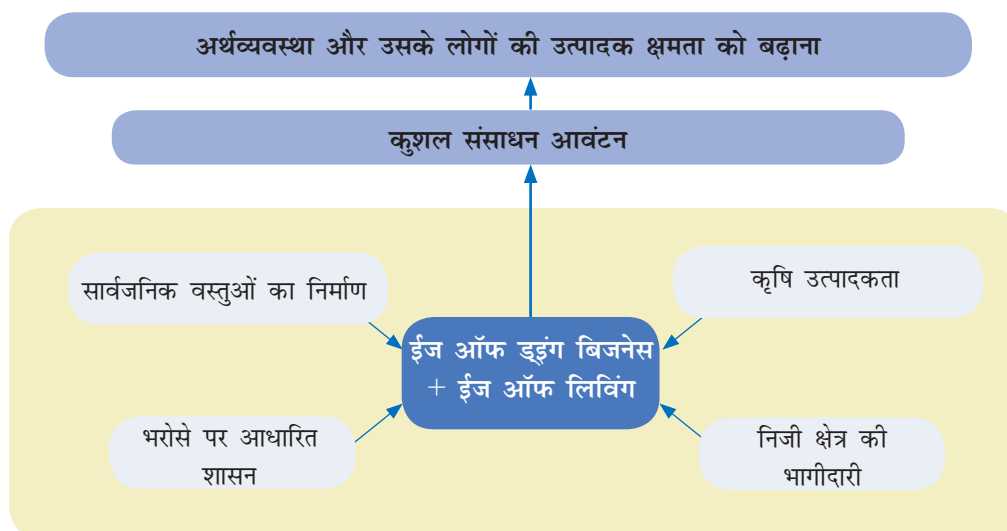
2003-08 के वैश्विक उछाल में भारत की भागीदारी

2.7 इन आघातों के समाप्त होने के बाद वर्ष 1998-2002 के सुधारों का विकास लाभांश देखा गया। संरचनात्मक सुधारों के वर्षों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास में योगदान देने और इससे लाभान्वित होने के लिए तैयार किया था। जबकि 2003-2008 के दौरान वैश्विक विकास औसतन 4.8 प्रतिशत रहा, भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन 8 प्रतिशत से अधिक बढ़ी। इस अवधि के दौरान आर्थिक विकास को मजबूत पूंजी प्रवाह (चित्र II.1) भी मिला गया था, जिसने अनुकूल घरेलू और बाहरी कारकों का संकेत दिया था। इनमें से कुछ में घरेलू आर्थिक गतिविधि में निरंतर गति, बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन, एक अनुकूल निवेश माहौल, पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत के लिए सकारात्मक भावना और वैश्विक तरलता की स्थिति/ब्याज दरों को प्रोत्साहित करना शामिल है।⁷ वर्तमान में आर्थिक विकास के अपने पिछड़े प्रभाव के साथ संरचनात्मक आर्थिक सुधारों का यह संयोजन भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर है।

नए भारत के लिए सुधार - सबका साथ सबका विकास

2.8 वर्ष 2014 से पहले किए गए सुधार मुख्य रूप से उत्पाद और पूंजी बाजार क्षेत्र के लिए किए गए थे। ये आवश्यक थे और इसे 2014 के बाद भी इन्हें जारी रखा गया। सरकार ने, हालांकि, पिछले आठ वर्षों में इन सुधारों को एक नया आयाम प्रदान किया। जीवनयापन और व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ाने और आर्थिक दक्षता में सुधार पर अंतर्निहित बल के साथ, अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि को और बढ़ाने के लिए सुधारों को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है। इन सुधारों का व्यापक सिद्धांत सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, विश्वास-आधारित शासन को अपनाना, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-साझेदारी करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। यह दृष्टिकोण सरकार की वृद्धि और विकास रणनीति में आमूल-चूल बदलाव को दर्शाता है, जिसमें विकास प्रक्रिया के विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी बनाने पर जोर दिया गया है, जहां प्रत्येक सुधार से विकास होता है और इसका लाभ मिलता है (सबका साथ, सबका विकास)।

चित्र II.6: डॉट-कॉम बबल संकट के कारण कई देशों में मंदी आई, जिससे वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई



2.9 जबकि वर्ष 2014 के बाद की अवधि में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था के लिए कई सामाजिक आर्थिक लाभ हुए हैं, यह अध्याय इन सुधारों के विकास-केंद्रित पहलुओं पर केंद्रित है। आगामी भाग में इस बात पर चर्चा

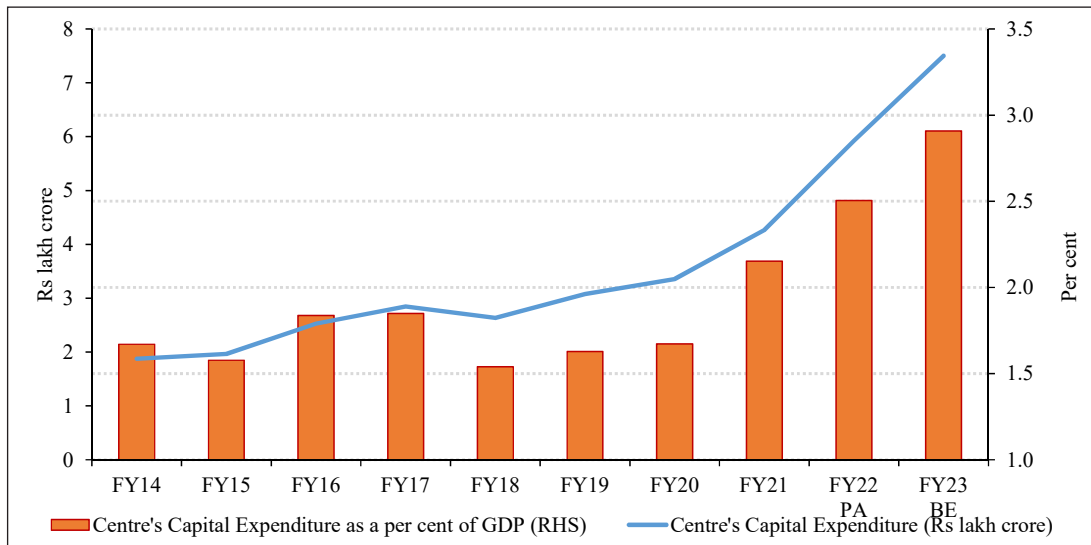
⁷मोहन, राकेश, (2008, कैपिटल फ्लो टू इंडिया, पृ. 235-263 में सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल एंडा, वित्तीय वैश्वीकरण और उभरते बाजार पूंजी प्रवाह, वॉल्यूम 144, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स), (<https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap44m.pdf>)

की गई है कि कैसे प्रत्येक सिद्धांत जो नए सुधार ढांचे को सहारा देता है, अर्थव्यवस्था और इसके लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में योगदान देता है। भारत के मध्यावधि विकास दृष्टिकोण में इनका गहन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

I. जीवन को आसान बनाने के लिए अवसरों, दक्षताओं संबंधी सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन करना

2.10 2000 के दशक में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरूआत भारत में बुनियादी ढांचा-गहन नीति निर्माण का शुभारंभ हुआ, जो एक और दशक तक धीमी गति से जारी रहा। पिछले कुछ वर्षों नीतिगत प्रतिबद्धता और बुनियादी ढांचे के परिव्यय में आई बड़ी उछाल अब (चित्र II.7) दिखाई दे रही है। जब बैलेंस शीट की समस्याओं के कारण गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र निवेश करने में असमर्थ थे, तब आर्थिक विकास को इससे सहायता मिली। ऐसा करके, सरकार ने आने वाले दशक के निजी निवेश और विकास में बढ़ोतरी के लिए एक अच्छा मंच तैयार किया है।⁸

चित्र II.7: केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ रहा है

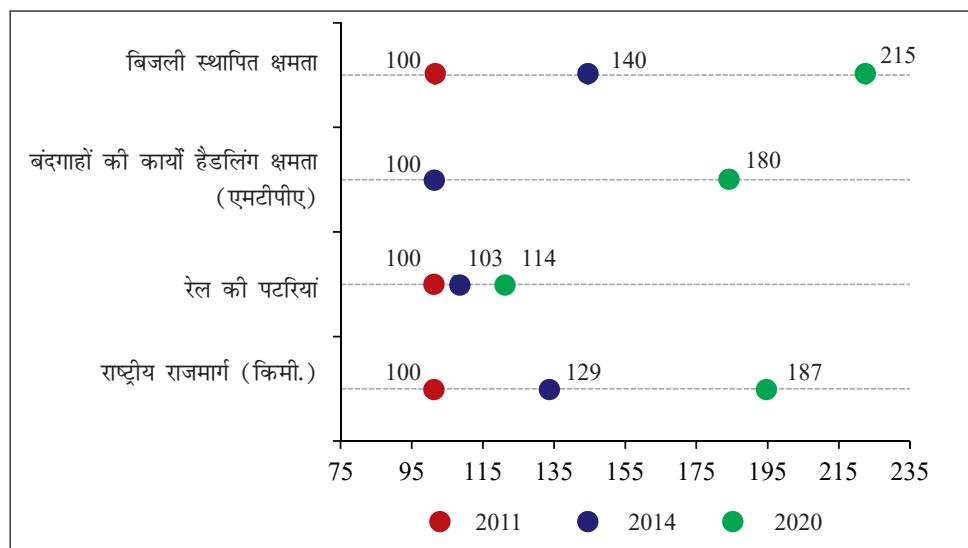


स्रोत: आरबीआई, एमओएसपीआई

2.11 सड़क संपर्क (भारतमाला), बंदरगाह अवसंरचना (सागरमाला), विद्युतीकरण, रेलवे उन्नयन, और नए हवाई अड्डों/हवाई मार्गों (उड़ान) के संचालन के लिए समर्पित कार्यक्रमों से पिछले कुछ वर्षों में भौतिक बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है (चित्र II.8)। भौतिक अवसंरचना के उन्नयन के विषय में विवरण अध्याय 12 में देखा जा सकता है। 2019 की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और 2021 की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन से, बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास के लिए एक मजबूत आधार रेखा तैयार की गई, जिससे बड़ी संख्या में विदेशी निवेश एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। 111 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचा निवेश 6,835 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ एनआईपी को लॉन्च किया गया था। यह 35 उप-क्षेत्रों की 9,000 से अधिक परियोजनाओं तक विस्तारित हो गया है और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। अपने अगले और पिछले सशक्त संबंधों, भौतिक अवसंरचना मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

⁸क्राउडिंग-आउट या क्राउडिंग-इन? पब्लिक एंड प्राइवेट इनवेस्टमेंट इन इंडिया, IMF वर्किंग पेपर (WP/15/264), दिसंबर 2015 (<https://www.imf.org/en/Publication/WP/issues/2016/12/31/Crowding-Out-or-Crowding-In-Public-and-Private-Investment-in-India-43470>)

चित्र II.8: महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षमता में विकास (पहले उपलब्ध मूल्य के साथ मान 100 के रूप में एक सूचकांक है)



स्रोत: मुद्रा और वित्त जून 2022 संबंधी आरबीआई की रिपोर्ट

नोट: (क) रेलवे ट्रैक रनिंग-ट्रैक किलोमीटरों को दर्शाता है

(ख): 2019 राष्ट्रीय राजमार्गों का डेटा, नवीनतम है और 2020 के लिए दिखाया गया है

2.12 सरकार द्वारा भौतिक बुनियादी ढाँचे पर जोर देने के अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढाँचे को तैयार करके उससे व्यक्तियों और व्यवसायों की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना एक गेम चेंजर रहा है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन में हाल ही में प्रकाशित एक लेख⁹ में अनुमान लगाया गया है कि भारत की मुख्य डिजिटल अर्थव्यवस्था 2014 और 2019 के बीच समग्र आर्थिक विकास का 2.4 गुना बढ़ी है। गैर-डिजिटल क्षेत्रों से इसके मजबूत जुड़ाव, डिजिटलीकरण विभिन्न चैनलों के माध्यम से संभावित आर्थिक विकास को मजबूत करता है। इनमें से कुछ, जैसे उच्च वित्तीय समावेशन, अत्यधिक औपचारिकता, बढ़ी हुई दक्षता और उन्नत अवसरों की चर्चा नीचे की गई है।

2.13 डिजिटल पहचान आधार के स्तंभों (पिलर्स) के आधार पर, पीएम-जन धन योजना के साथ बैंक खातों को जोड़ने और मोबाइल फोन (जेएएम ट्रिनिटी) की पहुंच के आधार पर, देश ने हाल के वर्षों में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बैंक खाता धारकों की संख्या 2015-16 के 53 प्रतिशत से बढ़कर 2019-21 में 78 प्रतिशत हो गई (एनएफएचएस के अनुसार)। अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों से यह पता चलता है कि विकास के मामले में समान स्तर वाले देशों के बैंक खातों धारकों की इतनी संख्या तक पहुँचने में लगभग आधी सदी लग गई है (डीसिल्वा और अन्य 2019)¹⁰ डिजिटल सत्यापन (ई-केवाईसी), डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल रिपॉजिटरी (डिजीलॉकर) और डिजिटल भुगतान (यूपीआई) जैसी कई डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं ने औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके और लेनदेन लागत को कम करके वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहित किया है¹¹ बड़ी संख्या में वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुंच, उच्च खपत और निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिससे उच्च आर्थिक विकास होता है। हाल ही में शुरू की गई कुछ डिजिटल पहलें, जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, छोटे व्यवसायों, ई-कॉमर्स मार्केट एक्सेस और क्रेडिट उपलब्धता के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे और मध्यावधि आर्थिक विकास को मजबूत करेंगी।

⁹धीरेंद्र गजभिए एट अल। (2022), 'भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का मापन', आरबीआई मासिक बुलेटिन दिसंबर 2022

¹⁰डीसिल्वा, डेरिल और फिल्कोवा, जुजाना और पैकर, फ्रैंक और तिवारी, सिद्धार्थ, द डिजाइन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर: लेसन्स फ्रॉम इंडिया (15 दिसंबर, 2019) बीआईएस पेपर नंबर 106 (<https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap106.pdf>)

2.14 अर्थव्यवस्था का बड़े पैमाने पर औपचारिकीकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'द इकोनॉमिस्ट' की एक रिपोर्ट (जनवरी 2023), भारत में कार्यबल की औपचारिकता के रुझान को दर्शाती है जो कि परिवर्तित डिजिटल वित्तीय वास्तुकला, डिजिटलीकृत जीएसटी प्रणाली और यूपीआई के उपयोग में वृद्धि के फलस्वरूप संभव हुआ है। आधार जैसी डिजिटल पहचान का निर्माण, असंगठित श्रमिकों का आश्रम पोर्टल पर पंजीकरण,¹² स्वनिधि पर रेहड़ी-पटरी वालों, जीएसटीएन पर कर भुगतान करने वाली फर्मों और उद्यम पोर्टल पर एमएसएमई के पंजीकरण ने औपचारिक रूप से इन समूहों को इकनॉमिक नेट में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के रूप में, अब हम देख सकते हैं कि उद्योग पोर्टल पर पंजीकृत 1.27 करोड़ उद्यमों में से, 93,000 से अधिक सूक्ष्म उद्यम अब छोटे उद्यम बन गए हैं, और 10,000 छोटे उद्यम पिछले दो वर्षों में मध्यम उद्यम बन गए हैं।¹³ इनमें से कई समूहों के लिए पहचान बनाने से औपचारिक ऋण तक उनकी पहुँच आसान हुई है। 32.7 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये का पहले ऋण का लाभ उठाया है, और इनमें से 6.9 लाख से अधिक ने 20,000 रुपये का दूसरा ऋण प्राप्त किया है। इसके अलावा, डिजिटल सिस्टम जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) और ई-वे बिल सिस्टम ने व्यापार लेनदेन की औपचारिकता को भी सबल किया है। जीएसटी करदाताओं¹⁴ की बढ़ती संख्या, वर्ष 2017 में 70 लाख से 2022 में 1.4 करोड़ से अधिक हो जाना औपचारिक व्यवसायों में विस्तार का संकेत देती है। यूपीआई की डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक उपयोग से छोटी से छोटी राशि के लिए भी लेनदेन को औपचारिक बनाना संभव हो गया है। अपने प्रचालनों में क्रेडिट और दक्षता लाभ की उन्नत पहुंच द्वारा व्यापक औपचारिकता से अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ेगी।

2.15 शासन की बाध्यकारी अडचनों को दूर किए जाने पर आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों से मिलने वाला लाभ अधिक महत्वपूर्ण होता है।¹⁵ विभिन्न पहलों/पोर्टलों को जोड़ने वाली एकीकृत डिजिटल इंटरफ़ेस ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में अधिक कुशल (दक्ष) संसाधन का आवंटन हुआ है। व्यापार संबंधी अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, केंद्र सरकार की क्रेडिट-लिंकड योजना के लिए जनसमर्थ पोर्टल, और केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं तक पहुंच के लिए उमंग ऐप मौजूदा प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से व्यापार करने में आसानी बढ़ाने की दिशा में आवश्यक कदम हैं। 28.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के साथ ईशराम पोर्टल का आसानी से उपयोग करने के लिए विभिन्न अन्य डिजिटल पोर्टलों के साथ एकीकृत किया गया है। पीएम गतिशक्ति, जीआईएस-आधारित एक प्लेटफॉर्म है जो मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए कई मंत्रालयों को एक साथ जोड़ता है, जिसका उद्देश्य रसद (लोजिस्टिक्स) लागत को कम करना है। इस प्रकार, डिजिटल प्रौद्योगिकियां सुधारों में सबसे आगे होने के कारण भारत के आर्थिक विकास को गति देने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति के बारे में अधिक जानकारी अध्याय 12 में देखी जा सकती है।

II. विश्वास-आधारित शासन

2.16 सरकार और नागरिकों/व्यवसायों के बीच विश्वास बढ़ने से निवेशक भावना में वृद्धि और व्यापार करने में सुगमता और अधिक प्रभावी शासन व्यवस्था से दक्षता में भी इजाजा होता है। पिछले आठ वर्षों के दौरान इस दिशा में लगातार सुधार किए गए हैं। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए) जैसे सुधारों के माध्यम से नियामक ढांचे के सरलीकरण से व्यापार करने में

¹²स्वॉलो, हक्सर, और पटनाम (2021), स्टैकिंग अप फाइनेंशियल इन्क्लूजन गेन्स इन इंडिया, IMF फाइनेंस एंड डेवलपमेंट (<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2021/07/india-stack-stack-financial-igqap&vkSj&fMftVy&inclusion.htm>) 'इमेजिन एन इंडिया विदाउट हॉकर्स', द इकोनॉमिस्ट जनवरी 2023

¹³<https://pqars.nic.in/annex/257/AU904.pdf>

¹⁴पीएमईएसी रिपोर्ट-'जीएसटी-बाकी बिंदुओं को जोड़ना', जून 2022

¹⁵आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक 2019

आसानी हुई है। आईबीसी ने परिसंपत्ति समाधान तंत्र की कुछ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पध्दतियों को आत्मसात किया है। इसके ईमानदार व्यापार किलताओं के लिए सम्मानजनक निकास तंत्र की व्यवस्था होती है और बेहतर संसाधन आवंटन के लिए स्ट्रेड एसेट्स में लॉक क्रेडिट को जारी (मुक्त) किया जा सकता है। यह बाजार-प्रेरित, पारदर्शी समाधान तंत्र वित्तीय प्रणाली में विश्वास पैदा करता है और कई नए निवेशकों को भारतीय व्यवसायों में निवेश करने के लिए आकर्षित करता है। आईबीसी की महत्वपूर्ण उपलब्धि डेब्टर-क्रेडिटर (देनदार-लेनदार) के संबंधों में लाया गया परिवर्तन भी है। दिवालियापन से बचने के लिए कर्जदार व्यक्ति से मुक्ति पाने के लिए तनाव जल्दी समाधान कर रहे हैं। 30 सितंबर 2022 तक, ₹7.3 लाख करोड़ की बुनियादी चूक वाले कॉर्पोरेट कर्जदारों के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में उनके प्रवेश से पहले ही 23,417 आवेदनों का निपटान किया गया था।¹²

2.17 एक अन्य नियामक सुधार, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (आरईआरए), रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शी लेनदेन की संस्कृति को विकसित कर रहा है।¹⁸ इस अधिनियम ने रियल एस्टेट ब्रोकरों और एजेंटों को नियामक के साथ पंजीकृत कर, विवादों के त्वरित निवारण के लिए तंत्र स्थापित करने और डेवलपर्स को समय पर अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए सक्षम बनाकर रियल एस्टेट क्षेत्र में बदलाव ला दिया है। देश भर में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरणों ने 1.06 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है। आरईआरए (आरईआरए) के अंतर्गत 99262 परियोजनाओं और पहले से पंजीकृत 71514 एजेंटों के पंजीकृत से यह अधिनियम इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है।

2.18 व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार, 2013 के कंपनी अधिनियम (तालिका II.2) के अंतर्गत किया गया है और इसके तहत 'मामूली आर्थिक अपराधों' का वैधीकरण किया गया है। सामान्य डिफॉल्ट से निपटने के लिए नागरिक देनदारियों (सिविल लायबिलिटीज) को शुरू करके, जिसमें धोखाधड़ी शामिल नहीं है या जहां चूक की प्रकृति विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक है, सरकार ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों की व्यापार करने की आसान व्यवस्था को बढ़ावा देने संबंधी अपने इरादे का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, अनुपालन के प्रति विश्वास-आधारित दृष्टिकोण कॉर्पोरेट संस्थानों में उद्यमियों का विश्वास पैदा करता है और उन्हें निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी व्यवसाय परम्परा को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सुधार के बाद, बिना कोर्ट का सहारा लिए अब तक 1400 से ज्यादा डिफॉल्ट के मामले निपटाए जा चुके हैं। साथ ही, कंपनी अधिनियम के तहत जुर्माने से बचने के लिए 4,00,000 से अधिक कंपनियों ने स्वेच्छा से पिछले चूक को ठीक किया है।¹⁹

तालिका 2: कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों के डिक्रिमिनालाइजेशन (वैधीकरण) का सैनैपशॉट

	गैर-अपराधीकरण से पहले	गैर-अपराधीकरण के बाद [दो चरणों में]
कुल दंड प्रावधान	134	124
शमनीय (संयोजनीय) अपराध [ज्यादातर जुर्माना लगाया जाता है]	81	31
अशमनीय (असंयोजनीय) अपराध [गंभीर अपराध, जहां सजा के कारावास का आदेश दिया जाता है]	35	35
नागरिक दायित्व के अधीन चूक (आंतरिक अधिनिर्णय तंत्र के माध्यम से)	18	58

¹⁶साहू, एमएस, और गुरु, ए. (2020)। भारतीय दिवाला कानून। विकल्प, 45(2), 69-78 (<https://www.ies.gov.in/pdfs/Indian-Insolvency-Law-Dr-MS-Sahoo-and-Dr-Anuradha-Guru.pdf>)

¹⁷IBBI तिमाही न्यूजलेटर (जुलाई-सितंबर 2022)

¹⁸निवेशक हित में सुधार-हालिया विधायी और विनियामक उपाय (2017) पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, आर. गांधी का भाषण

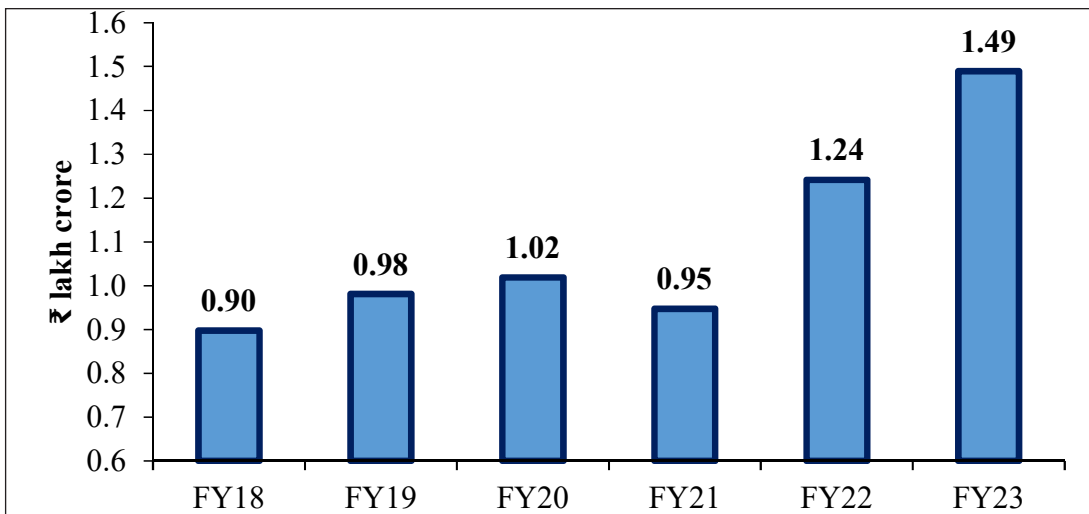
¹⁹कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम का उपयोग करना

2.19 नीतिगत अनिश्चितताओं के समाप्त होने से सरकार और उसके नागरिकों के बीच के विश्वास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 25000 अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त करके प्रक्रियाओं को सरल बनाना, 1400 से अधिक पुरातन कानूनों को निरस्त करना, एंजल टैक्स को समाप्त करना और भारत में स्थित संपत्तियों के अपतटीय अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर पूर्वव्यापी कराधान को हटाना, इत्यादि जैसे कदमों से सरकार की गैर-प्रतिकूल नीतिगत माहौल को सुनिश्चित करने के संकल्प दिखाई देता है। इन प्रयासों से निवेशकों की भावनाओं में सुधार हुआ है और विकास की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।

2.20 विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद, देश में कराधान पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) में काफी सुधार हुए हैं। कर नीति में सुधार जैसे एकीकृत जीएसटी को अपनाना, कॉर्पोरेट टैक्स दरों को कम करना, सॉवरन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को करों से छूट देना और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाना, जैसे कदमों से व्यक्तियों और व्यवसायों पर कर का बोझ कम हुआ है; और अर्थव्यवस्था से विकृत प्रोत्साहनों को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए, जीएसटी ने अनुपालन को कम करके व्यवसायों की मदद की है, राज्यों में माल का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया है, व्यवसायों के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग गोदाम रखने की आवश्यकता को समाप्त किया है और इस प्रकार व्यापार करना आसान हुआ है। पहले की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था उत्पत्ति आधारित थी, और इसने व्यवसायों के स्थान संबंधी विकल्पों को विकृत कर दिया था।

2.21 कर व्यवस्था के सुव्यवस्थितकरण के बावजूद, अर्थव्यवस्था में उच्च कर उछाल की सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। विख्यात अर्थशास्त्री इंदिरा राजारमन ने वर्ष 2019 में जीएसटी को 'एक राजस्व फलता' करार दिया; इसके बाद, सकारात्मक जीएसटी राजस्व संग्रह रुझान महामारी के बावजूद और भी मजबूत हुआ है। औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2018 में 0.90 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है (चित्र II.10)। साक्ष्य बताते हैं कि जीएसटी के बाद के काल में जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की उछाल में सुधार हुआ है (बॉक्स III.1, अध्याय 3)²⁰ चूंकि अन्य कर सुधार, जैसे कि महामारी के बाद की अनिश्चितता और व्यवधानों को देखते हुए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई जिसका प्रभाव कर संग्रहण पर धीरे-धीरे उच्च कर संग्रह के रूप में दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 19 की इसी अवधि के दौरान 10.3 प्रतिशत की लंबी अवधि की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में अप्रैल से नवंबर 2022 के लिए कॉर्पोरेट कर संग्रह में साल-दर-साल आधार पर 21.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चित्र II.10: औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि



स्रोत: राजस्व विभाग

²⁰2019 में मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चेलिया मेमोरियल लेक्चर के रूप में इंदिरा राजारमन द्वारा दिया गया द इवॉल्विंग जीएसटी शीर्षक वाला मोनोग्राफ। (<http://www.mse.ac.in/wp-content/uploads/2021/05/Monograph-43 ihMh,iQ>)

2.22 उच्च राजस्व उछाल का प्रमुख कारण कर प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालन बढ़ाना और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणालियों में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित कर प्रशासन सुधारों की शुरुआत करना है। फेसलेस मूल्यांकन और अपील प्रणाली को अब करदाताओं और आयकर विभाग के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एकीकृत डिजिटल सिस्टम की बहुल संबद्धता जांच संभव से कर चोरी को कम हुआ है। एक उदाहरण के रूप में, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तंत्र के परिणामस्वरूप बेहतर आय रिपोर्टिंग होती है, जिससे उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह होता है। इस संबंध में, सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा और सूचना साझा करने का निर्णय एक आशाजनक सुधार है और इसके परिणामस्वरूप कर प्रणाली में दक्षता लाभ होगा। ये सुधार भविष्य के आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था में भविष्य में संसाधन जुटाने के लिए शुभ संकेत देते हैं।

III. विकास में सह-भागीदार के रूप में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना

2.23 2014 के बाद की अवधि में सरकार की नीति का एक मूलभूत सिद्धांत विकास प्रक्रिया में को भागीदार निजी क्षेत्र को भागीदार के रूप में अपनाया है। पिछले आठ वर्षों में सरकार विनिवेश नीति को हिस्सेदारी की बिक्री और शेयर बाजार में पीएसई की फुल लिस्टिंग के साथ पुनर्जीवित किया गया है। वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष 23 (18 जनवरी 2023 तक) के दौरान, लगभग ₹4.07 लाख करोड़ की राशि विनिवेश से आय के रूप में 154 लेनदेन के माध्यम से विभिन्न तरीकों / उपकरणों से प्रयोग से प्राप्त की गई है। निजीकरण अभियान को फिर से शुरू करने के लिए एयर इंडिया का निजीकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। साक्ष्य से पता चलता है कि निजीकरण ने श्रम उत्पादकता में सुधार किया है और रणनीतिक क्षेत्रों तक कम करके उच्च दक्षता लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2.24 भारत की विनिर्माण क्षमताओं और उद्योगों में निर्यात को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रमों के तहत महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं। घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और विनिर्माण उद्योग में वैश्विक चैंपियन बनने के लिए महामारी के बाद क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) शुरू किए गए हैं। पीएलआई योजना मध्यम अवधि में उत्पादन, निर्यात और रोजगार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी; हालाँकि, समय के साथ ही इसका प्रभाव दिखाई देगा। पीएलआई के प्रभाव के शुरुआती अनुमान के अनुसार कुछ क्षेत्रों में उत्पादन रुझान हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना ने ₹4,784 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है और कुल उत्पादन ₹80,769 करोड़ (सितंबर 2022 तक)²² के निर्यात सहित ₹2.04 लाख करोड़ का योगदान दिया है। 1960-1990 में दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे पूर्वी एशियाई देशों के औद्योगीकरण के अनुभवों से विदेशी प्रतिस्पर्धा के बीच घरेलू औद्योगीकरण की सहायता करने के लिए समर्पित सरकारी नीति की सराहना की जा सकती है। इन देशों ने उद्योग के विकास के लिए आवश्यक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित अपने उच्च विकास चरण के दौरान अपने घरेलू उद्योगों की सहायता की।²³

2.25 आत्मनिर्भर भारत के तहत दिए जाने वाले उत्पादन प्रोत्साहन से घरेलू उत्पादन के विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलता है। पिछले आठ वर्षों में विदेशी निवेशकों के प्रति अपनाई जाने वाली नीति में और अधिक उदारिकरण देखा गया है, अधिकांश क्षेत्र अब स्वतः मार्ग के तहत 100: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के

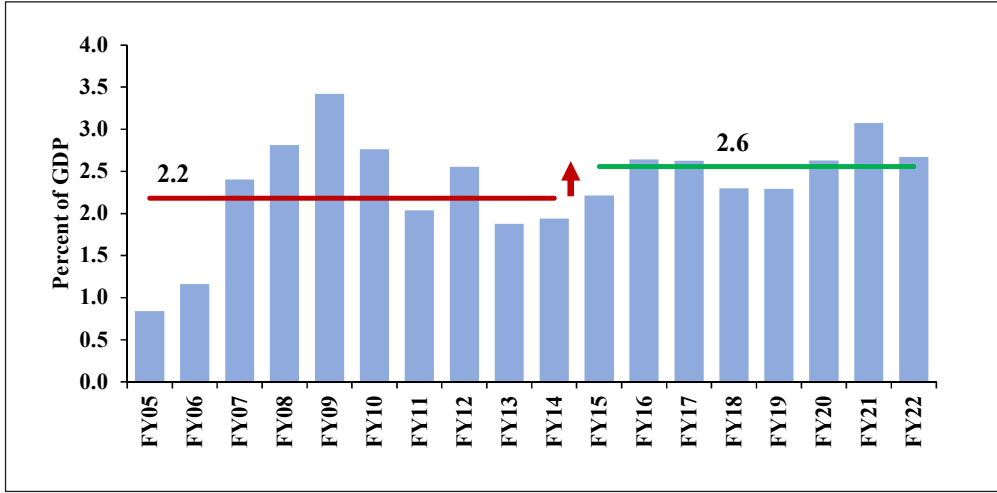
²¹छिब्र, अजय और गुप्ता, स्वाति, 2017। “बोल्डर विनिवेश या बेहतर प्रदर्शन अनुबंध? भारत के राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए कौन सा रास्ता,” वर्किंग पेपर्स 17/205, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक गवर्नेंस एंड पॉलिसी

²²<https://pib.gov.in/PressReleaseSelfframePage.aspx?PRID=1885189>

²³जोस्टीन हौज, 2020 “वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के युग में औद्योगिक नीति: दक्षिण कोरिया और ताइवान के औद्योगीकरण के अनुभवों पर एक विकासवादी ढांचे की ओर,” विश्व अर्थव्यवस्था, विली ब्लैकवेल, वॉल्यूम 43(8), पृष्ठ 2070-2092, अगस्त।

लिए खुले हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान भारत में सकल एफडीआई प्रवाह में स्पष्ट संरचनात्मक बदलाव आया है। भारत की सकल एफडीआई वित्त वर्ष 05-22 के दौरान जीडीपी का औसत 2.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2015-वित्त वर्ष 22 (चित्र II.10) में 2.6 प्रतिशत हो गया है। वित्त वर्ष 22 में 84.8 बिलियन अमरीकी डालर का उच्चतम वार्षिक सकल एफडीआई प्रवाह दर्ज किया गया। इन रुझानों से वैश्विक निवेशक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में भारत को वरीयता देते हैं।

चित्र II.10: 2014-15 के दौरान सकल एफडीआई/जीडीपी में संरचनात्मक बदलाव



स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की भारतीय रिजर्व बैंक पुस्तिका (एफडीआई डेटा); मौजूदा कीमतों पर अमेरिकी डॉलर जीडीपी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक आउटलुक डेटाबेस (अक्टूबर 2020)।

2.26 भारत को लागत प्रभावी उत्पादन केंद्र बनाने के लिए सरकार सक्षम बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। रसद की लागत को कम करने और इसे अन्य विकसित देशों के बराबर खड़ा करने के लिए एक व्यापक रसद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति (2022)²⁴ शुरू की गई है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के लिए रक्षा, खनन और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को खोलने से अर्थव्यवस्था में व्यापार के अवसरों में वृद्धि हुई है। निवेश प्रोत्साहन और आसान व्यापार अनुपालन ने स्टार्ट-अप के पोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 2016 में 452 से बढ़कर 2022 में 84,012 हो गई है। उद्योगों के सुधारों संबंधी अधिक विवरण अध्याय 9 में देखे जा सकते हैं।

2.27 हाल के वर्षों में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए किए जाने वाले सुधार औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के रूप में महामारी के दौरान एमएसएमई के लिए समर्थन उपायों और आत्मनिर्भर भारत के दायरे में एमएसएमई की परिभाषा में किए गए संशोधन ने उन्हें संकट के आघात का सामना करने में मदद की। ईसीएलजीएस, विशेष रूप से, पिछले दो वर्षों में 1.14 करोड़ एमएसएमई को लाभान्वित किया है, जिन्होंने ₹2.38 लाख करोड़ के संपार्श्विक-मुक्त ऋण का लाभ उठाया है। आगामी उपाय, जैसे एमएसएमई के लिए विलंबित भुगतानों को निपटाने के लिए टीआरडीईएस की शुरुआत, एमएसएमई के रूप में खुदरा और थोक व्यापारों को शामिल करना, और स्थिति में ऊपर की ओर बदलाव के मामले में तीन साल के लिए गैर-कर लाभों का विस्तार एमएसएमई ने एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए एक लचीला समर्थन प्रणाली बनाई है। एमएसएमई को अपनी मार्केटिंग जरूरतों और आसान भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच का भी लाभ मिला है। डिजिटल

²⁴अध्याय 12 में विवरण

कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के साथ एमएसएमई के लिए ई-कॉमर्स तकनीक का उपयोग करने और अपने लक्षित बाजारों में विविधता लाने के अवसर देने से, इस प्रवृत्ति के आगे और मजबूत होने की संभावना है। इसके अलावा, अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर एक वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में जी एसटीएन को ऑनबोर्ड करने से एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुंच के रास्ते खुलेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के अवसरों और उत्पादकता में वृद्धि के लचीले उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़े पैमाने पर निहितार्थ हैं, इस प्रकार यह उद्योग और अर्थव्यवस्था की विकास संभावनाओं को मजबूत करता है। इसलिए, ये सुधार जारी रहने चाहिए।

IV. कृषि में उत्पादकता बढ़ाना

2.28 पिछले छह वर्षों के दौरान भारत का कृषि क्षेत्र 4.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। यह वृद्धि आंशिक रूप से अच्छे मानसून के वर्षों और आंशिक रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों से हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई कोष, और जैविक और प्राकृतिक खेती जैसी नीतियों ने किसानों को संसाधनों के इष्टतम उपयोग और खेती की लागत को कम करने में मदद की है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) के विस्तार मंच के प्रचार ने किसानों को सशक्त बनाया है, उनके संसाधनों को बढ़ाया है और उन्हें अच्छा लाभ लेने में सक्षम बनाया है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) ने विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहायता की है। विशेष रूप से खराब होने वाली कृषि बागवानी वस्तुओं की आवाजाही को किसान रेल से पूरा किया जाता करती है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) ने बागवानी क्लस्टरों के लिए एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा दिया है। किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भी सहायता दी जा रही है। ये सभी उपाय कृषि उत्पादकता में वृद्धि का समर्थन करते हैं और मध्यम अवधि में समग्र आर्थिक विकास के योगदान को दर्शाते हैं।

2014 के बाद आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों की वापसी

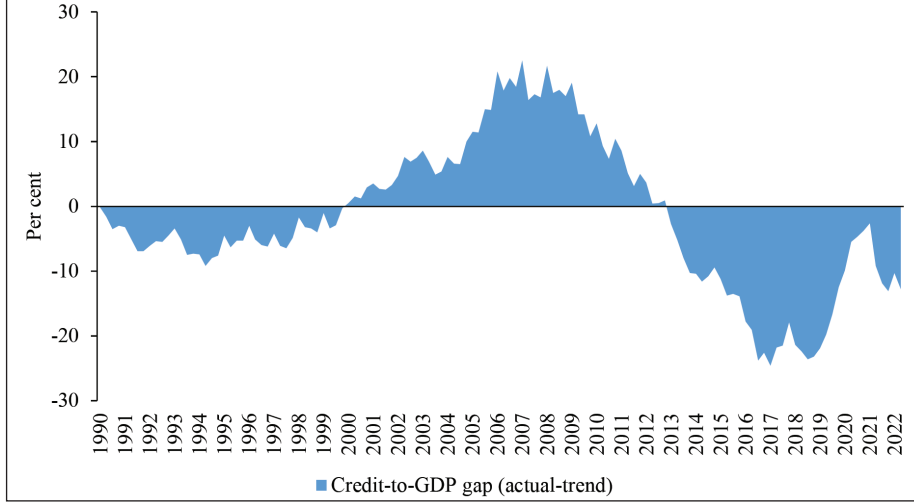
2014-22 के दौरान अर्थव्यवस्था को लगे आघात

2.29. सामान्य परिस्थितियों में, पिछले आठ वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में किए गए व्यापक और विस्तृत सुधारों (जैसा कि पिछले खंड में शामिल किया गया है) ने भारत के विकास को गति दी। किन्तु ऐसा नहीं था। पिछले वर्षों में क्रेडिट बूम के कारण भारत की बैलेंस शीट का स्ट्रेस इसके लिए 'दोषी' है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के आंकड़ों के अनुसार, भारत का गैर-वित्तीय निजी क्षेत्र का ऋण जीडीपी अनुपात मार्च 2004 में 72.9 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2010 तक 113.6 प्रतिशत हो गया। यह केवल छह वर्षों में 40.7 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। रुपये के संदर्भ में, गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा संचित ऋण की राशि लगभग 44 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 133 लाख करोड़ हो गई। यह छह साल में तिगुनी हो गयी। सीमित आर्थिक सुधारों के बावजूद, वैश्विक पूंजी प्रवाह और ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के बारे में आशावादी दृष्टिकोण से घरेलू ऋण और निवेश उछाल आया जो अंततः अस्थिर साबित हुआ, जैसा कि 2013 के दोहरे घाटे - राजकोषीय और बाहरी-संकटों से पता चलता है। केवल 2015 के बाद ऋण अनुपात से सार्थक रूप कम होना शुरू हुआ, तथा दिसंबर 2018 तक 83.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर गिर गया। आठ वर्षों में, इसने दिसंबर 2010 के 113.6 प्रतिशत से लगभग 30 प्रतिशत अंक की कमी की है।

2.30 अस्वाभाविक रूप से, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र का ऋण सहस्राब्दी के दूसरे दशक में अधिकांश समय के लिए अपने प्रवृत्ति मूल्य से लगातार कम था, जो जीडीपी अनुपात में ऋणात्मक अंतर को दर्शाता है (चित्र II.11)। 2017 में यह अंतर 25 प्रतिशत के अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। यह सकल एनपीए और ऋण वृद्धि के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नकारात्मक सहसंबंध (-0.5) दर्शाता है। उनकी

बैलेंस शीट में स्ट्रेस के कारण बैंकों की ऋण आपूर्ति दूसरे दशक²⁵ में गंभीर रूप से बाधित हुई। यह प्रवृत्ति क्रेडिट-टू-जीडीपी अनुपात के बड़े नकारात्मक विचलन की व्याख्या करती है।

चित्र II.11: अधिकांश 2010 के लिए जीडीपी गैप के लिए त्रैमासिक क्रेडिट नकारात्मक रहा



2.31 कंपनियों द्वारा किए गए निवेशों के फलीभूत नहीं होने के कारण, इसने बैंक ऋण चुकाने की उनकी क्षमता को क्षीण कर दिया। इसलिए, बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां बढ़ने लगीं। इसने पिछले दशक के उत्तरार्ध में वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र के बैलेंस शीट को ठीक करके दीर्घावधि गति दी। सरकार और आरबीआई ने 2010 के दौरान वित्तीय क्षेत्र को बैलेंस शीट के तनाव से उबरने में मदद करने के लिए कई नीतिगत पहलें कीं। इनमें से कुछ जैसे एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का कार्यान्वयन, 'संपत्ति गुणवत्ता समीक्षा' (एक्यूआर) की शुरुआत, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे की शुरुआत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूजीकरण (पीएसबी), और अन्य के बीच पीएसबी के विलय से बैंकों/कॉर्पोरेटों की बैलेंस शीट के समाशोधन करने में मदद मिली।

2.32 जब बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट में सुधार और सुधार होना शुरू हुआ, तो सितंबर 2018 में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड लीजिंग सर्विसेज (आईएलएण्डएफ) का पतन हो गया। यह एक बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) थी, जिसके पास एक विशाल संपत्ति का आधार था। इसके पतन का अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं पर भी भारी प्रभाव पड़ा। कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी डूब गईं। इसलिए, आवास ऋण वितरण बाधित हो गया। आमतौर पर, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां बैंकों की तुलना में अधिक उधारकर्ताओं और जोखिम वाले उधारकर्ताओं को उधार देती हैं। उन्हें बैंकों द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है। एक बड़ी एनबीएफसी आईएल एंड एफएस के पतन के बाद कुछ आवास वित्त कंपनियों के पतन के बाद उनका पुनर्वित्त पोषण कम हो गया। इसलिए, बैंक ऋण वृद्धि 2019 के अंत तक एकल अंकों में आ गई, जो 2020 तक जारी रही। कम ऋण वृद्धि और इसलिए कमजोर पूंजी निर्माण ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया।

2.33 सरकार ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती सहित आईएल एंड एफएस और हाउसिंग नइनेंस कंपनियों के पतन के नतीजों को रोकने के लिए कई उपाय किए। इसके तुरंत बाद, महामारी आ गई और सरकार को स्वास्थ्य, सामाजिक और अप्रत्याशित प्रकृति की आर्थिक स्थितियों का सामना किया। 2020-21 और 2021-22 के पिछले दो आर्थिक सर्वेक्षणों में इन पर विस्तार से चर्चा की गई है।

²⁵ ...

2014-2022 की अवधि 1998-2002 की अवधि के अनुरूप है

2.34 भारत का हालिया आर्थिक इतिहास इस स्थिति के समान है। 1998-2002 के दौरान, परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए थे लेकिन कम मात्रा में विकास लाभांश मिले (तालिका 11.3)। इस घटना को बाह्य कारकों और घरेलू वित्तीय क्षेत्र के समाशोधन से उत्पन्न के आघातों की श्रृंखला के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसने 1998 से 2002²⁶ तक के विकास रिटर्न को पीछे छोड़ दिया। 2003 में आघातों की समाप्ति के बारे में भारत ने वैश्विक उछाल में भाग लिया और उच्च दर से विकास किया। इसी तरह, वर्तमान संदर्भ में, महामारी के वैश्विक झटकों और 2022 में कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी के कम होने से, भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दशक में अपनी क्षमता से बढ़ने के लिए पूर्णतः तैयार है।

तालिका II.3: अवधियों के बीच समानांतर: 1998-2002 और 2014-2022

1998-2002	2014-2022
अर्थव्यवस्था को झटका	
<ul style="list-style-type: none"> परमाणु उपकरण परीक्षण 1998; प्रतिबंधों का पालन किया बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र तुलन-पत्रों को कम तरजीह देना करना और उनको ठीक करना लगातार दो सूखे प्रौद्योगिकी बस्ट; अमेरिकी मंदी और 09/11 	<ul style="list-style-type: none"> बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र की बैलेंस-शीट स्ट्रेस की अवधि महामारी के अभूतपूर्व आघात के बाद मुद्रास्फीति वैश्विक वस्तु मूल्य आघात के बाद वित्तीय स्थिति खराब हो गई
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार	
ब्याज दर विनियमन	अनूठी पहचान
निजीकरण	वित्तीय समावेशन
बैंकों के लिए संपत्ति वसूली	जीएसटी औपचारिकता की ओर ले जा रहा है
इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्वर्णिम चतुर्भुज)	दिवालियापन और दिवालियापन संहिता
एफआरबीएम अधिनियम	निजीकरण
	कर दरों का युत्तिकरण और कर प्रशासन (ईओडीबी) सुधार;
	अपराधों का विमुद्रीकरण
	टीके रोल-आउट
	व्यय प्रबंधन सुधार
	आत्मनिर्भर
	पब्लिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर
ग्रोथ रिटर्न	
<ul style="list-style-type: none"> एक बार संरचनात्मक सुधारों ने आघातों की समाप्ति के बाद 2003 से विकास लाभांश का भुगतान किया 	<ul style="list-style-type: none"> वित्तीय क्षेत्र में बैलेंस शीट मजबूत; कॉर्पोरेट क्षेत्र में लगभग 30 प्रतिशत अंक (ऋण/जीडीपी अनुपात) की कमी वैश्विक आघातों से निपटने के दौरान मैक्रो-इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर जोर

²⁶विवरण के लिए इस अध्याय के अनुच्छेद 6 का संदर्भ लें

इस दशक में ग्रोथ मैग्नेट (2023-2030)

एकबारगी आघातों से उबरने के बाद भारत अपनी क्षमता से वृद्धि के लिए तैयार है।

2.35 वित्तीय और कार्पोरेट क्षेत्र में तुलन पत्र के सुधार की एक लंबी अवधि के बाद वित्तीय चक्र आगे की दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है। इसके अतिरिक्त महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक आघातों और 2022 की समाप्ति के समय में वस्तु मूल्यों में बढ़ोत्तरी से भारतीय अर्थव्यवस्था 2003 के बाद के वृद्धि संबंधी अनुभव की तरह आने वाले दशक में अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ने को तैयार है। भारत के वृद्धि दृष्टिकोण को पूर्व महामारी वर्षों से बेहतर होने की संभावना का प्राथमिक कारण यही है। पिछले कुछ वर्षों में विकसित और स्वस्थ वित्तीय प्रणाली ने प्रभावी ऋण सुविधा, उच्चतर निवेशों और उपयोग के माध्यम से आने वाले वर्षों में उच्चतर वृद्धि में योगदान दिया है। भला हो भारत की डिजिटल क्रांति और औपचारिकरण का, जिससे बैंक पहले की अपेक्षा अपने ग्राहकों के ऋण जोखिमों की अधिक सूचना रखते हैं। जिससे वे ऋण देने और मूल्य निर्णयों को पहले से बेहतर बनाने में सक्षम हों। यह पहले से स्वास्थ्यकारी और लंबे ऋण चक्र बनाने को सुगम बनाएगा। बैंक क्रेडिट वृद्धि अब से कुछ समय पहले से दो अंकों में रही है। 2012 से भारत में एक हालिया आईएमएफ कार्यरत अखबार ने क्रेडिट-से-जीडीपी अनुपात अंतर, बैंक तुलन पत्रों और जीडीपी विकास में रूझानों का विश्लेषण किया है और उच्चतर क्रेडिट वृद्धि में बेहतर पूंजीकृत बैंकों के परिणाम को दर्शाता है, जो आगे चलकर उच्चतर जीडीपी वृद्धि में रूपांतरित करेगा।

2.36. उच्च वित्तीय समावेशन, और अधिक आर्थिक अवसरों के संदर्भ में डिजिटलीकरण सुधार और अधिक औपचारिकता, परिणामी दक्षता लाभ मध्यम अवधि में भारत के आर्थिक विकास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चालक होगा। भारत के लिए अपनी हालिया अनुच्छेद IV रिपोर्ट में, आईएमएफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत द्वारा व्यापक सुधारों के फल कार्यान्वयन और डिजिटलीकरण से भारत की मध्यम अवधि की विकास क्षमता को अपेक्षित लाभांश से अधिक बढ़ा सकता है। कौशलतात्मक पहलों सहित सरकार द्वारा की गई विविध उत्पादकता-संवर्धन सुधार आने वाले वर्षों में की गई विविध पहलों ने भारत की वृद्धि क्षमता को और दृढ़ किया है, और यह एकबारगी झटकों के प्रभावों के रूप में वास्तविक जीडीपी में दिखाई देगा।

2.37 इसके अलावा, उभरती हुई भू-राजनीतिक स्थिति भारत के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण से लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करती है। पिछले कुछ वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को वैश्विक व्यापार तनाव, महामारी से प्रेरित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और यूरोप में संघर्ष के कारण अभूतपूर्व जोखिम का सामना करना पड़ा है। फर्मों को अपने उत्पादन को एक ही देश में केंद्रित करने के जोखिम से अवगत कराया गया था। इसलिए, वैश्विक नीति की अनिश्चितता को देखते हुए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां धीरे-धीरे अपने उत्पादन आधारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की रणनीति तलाश रही हैं। यूएनसीटीएडी ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया है कि 'पुनर्स्थापन, विविधीकरण और क्षेत्रीयकरण आने वाले वर्षों में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के पुनर्गठन को बढ़ावा देंगे'³⁰ सक्षम नीतिगत ढाँचे के साथ, भारत स्वयं को अन्य देशों से पूंजी विविधीकरण के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।^{31 32}

²⁷उभरती अर्थव्यवस्थाएं लंबे समय तक उत्पादकता में मंदी का सामना कर रही हैं, 'द इकोनॉमिस्ट' 16 जनवरी 2020 longed-productivity-slowdown, 4 फरवरी 2020 को देखा गया)

²⁸फ्रेडरिक बोड्स, 'फैब्रिस कोलार्ड, और स्मेट्स, बूम और प्रणालीगत बैंकिंग संकट, यूरोपीय सेंट्रल, यूरोपीय सेंट्रल बैंक वर्किंग पेपर नंबर 1514 फरवरी 2013 (<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1514.pdf>)

²⁹स्टीफन जी॰ सेचेती और मैरियन कोहलर और क्रिश्चियन अपर, 2009 "वित्तीय संकट और आर्थिक गतिविधि," एनबीईआर वर्किंग पेपर्स 15379, नेशनल ब्यूरो ऑफ़ इकोनॉमिक रिसर्च, इंक।

³⁰मुदुली, एस और बेहरा, एच., 2021 भारत में बैंक कैपिटल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि अर्थशास्त्र और वित्त, पीपी. 1.251 (<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/1MACROECONOMIC3C3EEF439E4C49459A3C9EB4011B3B39>)

³¹मार्गाक्स मैकडोनाल्ड द्वारा भारत में वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक विकास; टेंगटेंग जू (जुलाई 2022) <https://www.imf.org/en/Publications/WP/issues/2022/07/08/Financial-Sector-and-Economic-Growth-in-india-520580>)

³²वास्तविक अनुपात और उसके रूझान मूल्य के बीच अंतर

हाल ही में प्रकाशित चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक 2023 (विश्व आर्थिक मंच) ने भारत को इन वैश्विक रुझानों से लाभ उठाने के बारे में प्रकाश डाला है।³³

2.38 पिछले आठ वर्षों में किए गए नए युग के सुधार एक लचीले, साझेदारी-आधारित शासन पारिस्थितिकी तंत्र की नींव हैं और सुदृढ़ रूप से बढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता को बहाल करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है कि आर्थिक विकास में तेजी और संधारणीयता आ सके उससे एक बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन मिल सके। अनुपालनों का विनियमन और सरलीकरण लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन व्यवस्था को पूरी तरह से विघटित करना जारी रखेगा। राज्य सरकारों को बिजली क्षेत्र के मुद्दों का समाधान करना होगा और डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं को दूर करना होगा। आधुनिक उद्योग और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए शिक्षा और कौशल पर जोर दिया जाना चाहिए, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण जैसी इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटना चाहिए और भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने की पहल जारी रहनी चाहिए। बढ़ते मोटापे के स्तर को रोकने और उसे कम करने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए।³⁴ ऊर्जा संक्रमण और विविधीकरण के लिए आवश्यक आवश्यक धातुओं और खनिजों को सुरक्षित करने के लिए दूरगामी योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम से व्यापक दक्षता लाभ लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति मुद्रीकरण योजना को सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जाने चाहिए। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को कम करने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण राजस्व का उपयोग किया जाता है, तो क्रेडिट रेटिंग में उत्तम सुधार होगा, जिससे पूंजी की लागत कम होगी। यह अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा राजकोषीय प्रोत्साहन होगा। एमएसएमईएस पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुधार, वित्त और कार्यशील पूंजी तक उनकी पहुंच बढ़ाने और उन्हें अपने व्यवसायों को जिम्मेदारी से विकसित करने के लिए कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण से लैस करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। राज्य सरकारों को विभिन्न कारक बाजार सुधारों को पूरा करने के विभिन्न चरणों में निर्णायक प्रगति करनी चाहिए।

2.39 इस अध्याय में हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपना उत्साह नहीं खोया था, न ही सरकारी सुधार ने उनकी प्रभाविकता मापी थी। वित्तीय और कार्पोरेट क्षेत्र में तुलन पत्र में स्ट्रेस के न होने से भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वृद्धि कर सकती थी। नए दशक में बेहतर और स्वास्थ्यकर तुलन पत्रों का लाभ उठाने के लिए हम अर्थव्यवस्था में आगे की ओर देख रहे थे, यह वैश्विक महामारी द्वारा स्वरूचि के बाद खाद्य, ईंधन और खाद के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई थी। नकारात्मक आघात अवश्य कम हो जाएंगे जैसा कि उन्होंने नई सहस्राब्दी के प्रारंभिक वर्षों में किया था। उधार लेने और उधार देने की इच्छुक है। इसलिए, यह अवश्यम्भावी है कि इन सुधारों के प्रभाव अब और स्पष्ट होंगे। एक पुनर्स्थापित क्रेडिट चक्र भारतीय निजी क्षेत्र के कैपेक्स चक्र को फिर से जीवंत करेगा। यह अकेले ही भारत को वास्तविक रूप से कम से कम 6 प्रतिशत दर प्रतिवर्ष बढ़ने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। उसके शीर्ष पर, पिछले 6-7 वर्षों में बनाए गए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे से उत्पन्न उच्च आर्थिक दक्षता भी संभावित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 30-50 आधार अंक जोड़ देगी। भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की परिपक्वता के विकास प्रभावों को अपर्याप्त रूप से समझा गया है। औपचारिकता और सक्षम वित्तीय समावेशन, इतने स्पष्ट हैं कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह समय की बात है कि इसकी वृद्धि डाटा पर पड़ने वाले प्रभावों से पहले सशक्त हो जाए। यही कारण है कि भारत की मध्यावधि में जीडीपी वास्तविक वृद्धि 6.5 प्रतिशत की औसत से प्राप्त करने की संभावना है। इसके अलावा, अगर आने वाले वर्षों में पिछले पैराग्राफ में बताए गए अन्य सुधारों को आगे बढ़ाया जाता है, तो मध्यम अवधि में भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि 7-8 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ सकती है।

³³<https://www.imf.org/en/Publications/CR/issues/2022/12/21/India-2022-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-527283>

³⁴विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 (<https://uncatad.org/news/covid-19-will-likely-transform-global-production-says-un-report>; दस्तावेज/पत्र 2020 en.pdf)